

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 428 / 2024

डॉ. नीतू

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद, योग एवं नेचूरोपैथी, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, आयुर्वेद, योग एवं नेचूरोपैथी, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. डॉ. विवेक मोहन गुप्ता, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी ग्रेड द्वितीय, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर राजकीय होम्योपैथिक मोबाइल यूनिट, जयपुर पदस्थापित।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.02.2024

आदेश की दिनांक : 06.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद पर राजकीय होम्योपैथिक मोबाइल यूनिट, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, जनाना अस्पताल, भरतपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का पूर्व में आदेश दिनांक 17.02.2023 के द्वारा स्थानान्तरण किया गया था, जिसको अधिकरण में अपील संख्या 1047/2023 को चुनौती देते हुये अधिकरण द्वारा दिनांक 02.03.2023 को स्थगन आदेश जारी किया गया था, जो वर्तमान में अपील लम्बित रहना बताई गई है और

अपील लम्बित रहते हुये अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को युक्तियुक्त नहीं माना है। अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के स्थान पर और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से आदेश जारी किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में कार्यरत हैं और स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि पति-पत्नी दोनो राजकीय सेवा में कार्यरत हों तो उनका स्थानान्तरण एक ही स्थान अथवा नजदीकी स्थान पर किया जाना चाहिये। अपीलार्थी के परिवार में श्री रामपाल हृदय रोग जैसी बीमारी से पीडित है, जिनका उपचार नारायणा हॉस्पिटल में हो रहा है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुये अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो उक्त विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड द्वितीय के पद पर राजकीय होम्योपैथिक मोबाइल यूनिट, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, जनाना अस्पताल, भरतपुर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552)** में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :-

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)